योजना	1994-95	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना	737.46	182.99	209.29
सुनिश्चित रोजगार योजना	180.00	280.00	320.00
दस लाख कुओं की योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया		72.64
इंदिरा आवास योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।		162.10
राष्ट्रीय सामजिक सहायता कार्यक्रम	-	41.11	37.75
महिला एवं बाल विकास योजना			0.50

*अनन्तिम

इन जिलों सहित देशभर के ग्रामीणा निर्धनों के उत्थान के लिए विभिन्न स्तरो पर इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती हैं।

(च) मंत्रालय द्वारा देश में प्रसे, विज्ञापन, दूरदर्शन, आकाशवाणी बाहरी प्रचार जैसे समस्त उपलब्ध माध्यमों के जरिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तारित करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा चलो गांव की ओर और गांव विकास की ओर जैसे दो पाक्षिक आकाशवाणी कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया गया हें। इन आकाशवाणी कार्यक्रमों को गुजराती में भी प्रसारण किया जा रहा हैं। बनासंकाठां को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को भी अन्त वैयक्तिक सम्पर्क और परम्परागत माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 5.00 लाख रूपए की अनुदान सहायता दी गई थी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर

106. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं असम के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले पाचं वर्षो के दौरान किए गए प्रयत्नों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। स्वरोजगार योजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसकी उप योजनाएं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, ट्राईसेम और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति शामिल हैं। मजदूरी रोजगार योजनाओं में जवाहर योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना शामिल हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के पहचान किए गए ग्रामीण गरीबों को सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी ऋण के रूप में सहायता दी जाती हैं। इस वित्तीय सहायता से प्राप्त परिसंपत्तियों से स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। उनमें वृद्वि होती हैं। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिंद्वातों में यह प्रावधान हैं कि 40% लाभार्थी महिला होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण गरीब महिलाएं स्वयं डवाकरा समूह बनाती हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को आय सर्जक ऐसी गतिविधियों शुरू करने के लिए 25,000 रू. की परिक्रामी निधि प्राप्त होती हैं जो कि उनकी रूचि और कौशल के अनुरूप हों।

ट्राईसेम का उदेश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उदयमी कौशल

प्रदान करना हैं ताकि उन्हे कृषि और संबद्व गतिविधियो उघोगों, सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों में क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार शुरू करने योग्य बनाया जा सकें। 40% लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति योजना का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट प्रदान करना हैं ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो और उनके उत्पादन और आय में वृद्वि हो।

जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बेरोजगार और कम रोजगार वाले व्यक्तियो के लिए लाभप्रद अतिरिक्त रोजगार पैदा करना हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रमीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से स्वरूथ ऐसे सभी व्यक्तियों को कम कृषि कार्य वाले मौसम के दौरान लाभप्रद रोजगार प्रदान करना हैं, जिन्हे कि इस कार्य की जरूरत हैं और जो इच्छुक हैं परंतु जिन्हे कार्य नहीं मिल रहा हैं। यह मांग-आधारित योजना हैं। प्रति परिवार अधिकतम दो वयस्को को 100 दिनों का रोजगार आश्वासन दिया जाता हैं।

पिछले पांच वर्षो में मध्य प्रदेश, राजस्थान ओर असम राज्यों की उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्र विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश राजस्थान और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षो (1992-93 --- 1996-97) के दौरन प्राप्त उपलब्धिं

1. समन्वित ग्रमीण विकास कार्यक्रम

क्रम सं.	राज्य का नाम	महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	219178
2.	राजस्थान	160224
3.	असम	57395

1.

2. ग्रामीण क्षेत्रो में महिला और बाल विकास

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मित समूहों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	5600
2.	राजस्थान	2613
3.	असम	3577

3. ट्राइसेम

क्रम. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	73277
2.	राजस्थान	29599
3.	असम	24738

4. ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति

क्रम. सं.	राज्य का नाम	उपलन्धि
1.	मध्य प्रदेश	29292
2.	राजस्थान	26326
3.	असम	22919

5. **जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)**

(लाख श्रम दिन)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार
1.	मध्य प्रदेश	1292.39
2.	राजस्थान	475.53
3.	असम	96.35

6. **सुनिश्चित रोजगार योजना**

(लाख श्रम दिन)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार
1.	मध्य प्रदेश	454.00
2.	राजस्थान	320.02
3.	असम	47.12

Benefits under Rural Works Programmes

107. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAM
CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) apart from the primary benefits under the Rural Works Programmes like the JRY, PMRY, EGS, what are the secondary benefits gained due to these programmes;

(b) whether any study has been made of these secondary benefits; and

(c) the steps being taken to enhance the efficiency of all the Rural Works Programmes?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU); (a) The EGS is a State Government schemes implemented in Maharashtra. However, the Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS) and Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) are Centrally Sponscred Schemes. The secondary benefits cf JRY and EAS is to create economic infrastructure and community assets for sustained employment in the rural areas. Under the PMRY, the secondary objective of the scheme is to provide employment to at least one more person in the enterprise set-up.

(b) Two rounds of concurrent evaluations in respect of JRY were carried out by reputed & independent research institutions for the period January—December, 1992 and May, 1993 to June, 1994. The evaluation of PMRY is under execution. No evaluation study has been conducted in respect of EAS.

(c) For effective implementation of these programmes, the guidelines lay emphasis on physical monitoring of these programmes through field inspections by the State and Central Government officers. The States are also required to constitute monitoring and vigilance committees at village, block, district and State levels to supervise, monitor and review rural development programmes.

Assets created under various Rural Works Progammes

108. DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to s«te:

(a) the total value of assets created uptill now under all the Rural Works i Programmes taken together such as JRY, EGS, etc.;

(b) whether these assets have any impact on the agricultural growth in the rural areas, and if so, to what extent;

(c) the general arrangements made for the maintenance and upkeep of these assets; and

(d) the total target of creating assets under the various RWPs in the next five years?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) The EGS is a State Government scheme implemented in Maharashtra. However, under the major Centrally Sponsored wage employment schemes like JRY, EAS, MWS and IAY, Rs. 31793.50 crores.

(upto 1996-97) have been utilized for creation of assets alongwith the generation of employment in the form of casual manual labour.